

IV. मौद्रिक तथा चलनिधि स्थितियां

बारीकी से समायोजित तथा एहतियाती उपायों के चलते 2012-13 के दौरान चलनिधि की स्थितियां सहज हुईं। किये गए उपायों में खुला बाजार परिचालन तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात दोनों में की गई कटौती थी। रिजर्व बैंक ने वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल 2012 में रिपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की। परंतु, मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर बने रहने को देखते हुए उसके बाद उसने नीति दरें अपरिवर्तित रखीं। जहां 2012-13 की दूसरी तिमाही में रिजर्व मुद्रा की वृद्धि दर में गिरावट आई तथा व्यापक मुद्रा की वृद्धि दर पूर्ववत् रही, वहीं सकल जमाराशि तथा खाद्येतर ऋण की वृद्धि दर सांकेतिक दायरे से नीचे रही। आगे चलकर, सीआरआर में कटौती के दूसरे दौर का प्रभाव, चलनिधि की समुचित स्थितियां एवं ऋण की मांग में मौसमी वृद्धि मौद्रिक समुच्चयों को प्रभावित कर सकती है, जबकि मौद्रिक चक्र का अनुमानित पथ उभरते वृद्धि-मुद्रास्फीति के आपसी संबंधों से निर्धारित होगा।

वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के आपसी संबंधों के अनुसार मौद्रिक नीति में बारीकी से समायोजन करते हुए रिजर्व बैंक ने ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए चलनिधि डाली

IV.1 रिजर्व बैंक ने वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के उभरते आपसी संबंधों के अनुरूप अपनी मौद्रिक नीति में बारीकी से समायोजन किया। पिछले दो वर्षों में मुख्यतः मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीति प्रत्याक्षाओं को नियंत्रित करने के लक्ष्य संबंधी नीतिगत रूझान में मूलतः परिवर्तन किये बिना रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता रहा है कि चलनिधि की स्थितियां अत्यधिक कठोर न हों। 2012-13 में अब तक खुले बाजार से सीधी खरीद के जरिए ₹800 बिलियन की चलनिधि डाली जाने के साथ-साथ 2011-12 की चौथी तिमाही में सीआरआर में 125 आधार अंकों एवं सितंबर 2012 में 25 आधार अंकों की कटौती के जरिए चलनिधि बढ़ायी जाने के परिणामस्वरूप 2011-12 की तुलना में 2012-13 में चलनिधि की स्थितियां सहज रहीं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त 2012 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में 100 आधार अंकों की कमी की, इस उपाय से निजी ऋण में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने सितंबर 2012 में राजकोषीय समेकन के कतिपय उपायों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल में वर्ष की शुरुआत में नीति दर में 50 आधार अंकों की कटौती की (चार्ट IV.1)।

IV.2 सीआरआर, खुला बाजार परिचालन तथा एसएलआर के जरिए सक्रिय चलनिधि परिचालन के चलते चलनिधि की स्थितियां मोटे तौर पर नीतिगत लक्ष्यों के अनुरूप रहीं। नीतिगत लक्ष्यों में ये

सारणी IV.1: प्रमुख नीतिगत दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

प्रभावी होने की तारीख	रिपो दर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात	सांविधिक चलनिधि अनुपात
1	2	3	4
3 मई 2011	7.25 (+0.50)	6.00	24.0
16 जून 2011	7.50 (+0.25)	6.00	24.0
26 जुलाई 2011	8.00 (+0.50)	6.00	24.0
16 सितंबर 2011	8.25 (+0.25)	6.00	24.0
25 अक्टूबर 2011	8.50 (+0.25)	6.00	24.0
28 जनवरी 2012	8.50	5.50 (-0.50)	24.0
10 मार्च 2012	8.50	4.75 (-0.75)	24.0
17 अप्रैल 2012	8.00 (-0.50)	4.75	24.0
11 अगस्त 2012	8.00	4.75	23.0 (-1.00)
22 सितंबर 2012	8.00	4.50 (-0.25)	23.0

टिप्पणी: 1. रिपो चलनिधि के अंतर्वेशन को दर्शाता है।

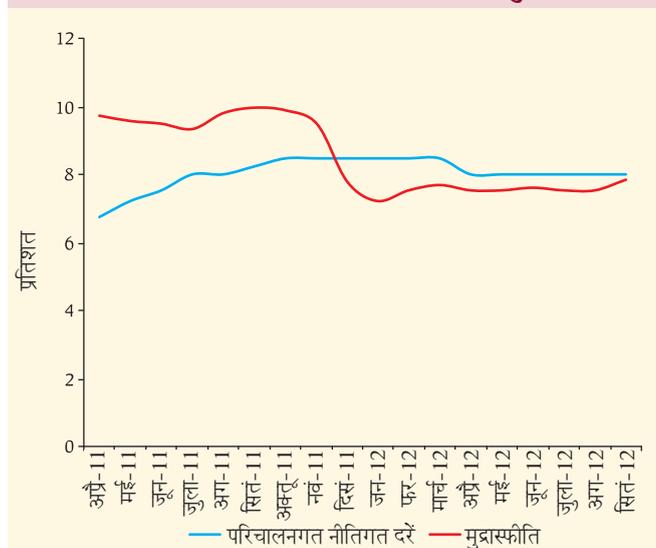
2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत अंकों में नीति दरों में परिवर्तन को दर्शाते हैं।

बातें शामिल थीं - मुद्रास्फीति का रिजर्व बैंक के प्रत्याशित स्तर से काफी उच्चतर स्तर पर बना रहना एवं इस बात को सुनिश्चित करना कि ऋण की आपूर्ति उत्पादन की जरूरतों के लिए बाधक न हो।

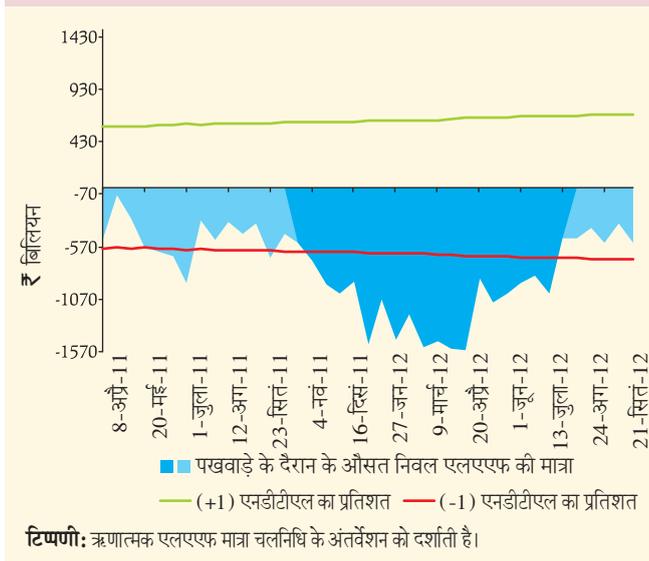
स्थितियां संतोषजनक चलनिधि के दौर में आ गयीं

IV.3 2011-12 से चलनिधि की स्थितियों को मोटे तौर पर तीन स्पष्ट दौर में बांटा जा सकता है। पहले दौर में अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2011 तक रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे में रहने

चार्ट IV.1: परिचालनगत नीतिगत दरें और मुद्रास्फीति



चार्ट IV.2: चलनिधि की स्थिति



के बाद चलनिधि की कमी एनडीटीएल के एक प्रतिशत से अधिक हो गयी (चार्ट VI.2)। चलनिधि में भारी कमी मुख्यतः विदेशी मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप एवं ऋण तथा जमाराशि की वृद्धि दरों में बढ़ते अंतर के कारण थी। कमी की स्थिति अस्थायी कारकों के चलते और बिगड़ गयी। इन कारकों में रिजर्व बैंक के पास सरकार की नकद राशि में बढ़ोतरी होना और इसके सामान्य से अधिक समय तक बना रहना एवं मुद्रा के परिचालन में वृद्धि होना था।

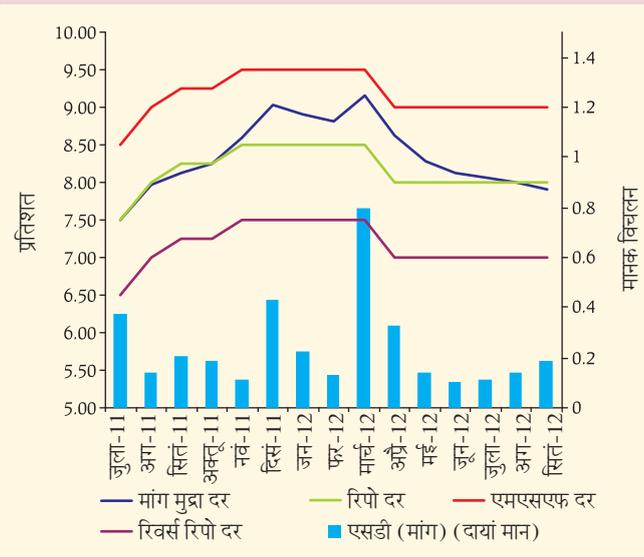
IV.4 वित्तीय प्रणाली को चलनिधि का बेहतर आधार प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक को चलनिधि का प्रबंधन सक्रियता से करना पड़ा, साथ ही मुद्रास्फीति के दबावों के फिर से उभरने के जोखिम के प्रति भी सतर्क रहना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप 2012-13 की पहली तिमाही में चलनिधि की स्थितियां काफी सहज हो गयीं एवं चलनिधि की कमी की मात्रा जुलाई 2012 से मोटे तौर पर रिजर्व बैंक के अपेक्षित स्तर तक आ गयी और यहां से तीसरे दौर की शुरुआत होती है। 2012-13 की दूसरी तिमाही में स्थिति में बदलाव आने के तीन प्रमुख कारण थे- खुला बाजार परिचालनों के जरिए चलनिधि डाला जाना, मुद्रा के परिचालन में गिरावट तथा रिजर्व बैंक के पास सरकार की नकद शेष राशि में आयी गिरावट। जून 2012 की मध्य तिमाही समीक्षा में निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा में वृद्धि किये जाने के बाद बैंकों द्वारा इसका व्यापक उपयोग किये जाने एवं 31 जुलाई 2012 को एसएलआर में 1 प्रतिशत की कटौती की घोषणा ने भी चलनिधि की स्थितियों में सुधार लाने में मदद की।

IV.5 जून 2012 की तुलना में जुलाई 2012 में चलनिधि की स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत औसत दैनिक चलनिधि अंतर्वेशन की राशि लगभग ₹480 बिलियन थी जिसमें अगस्त 2012 में और मामूली गिरावट आयी। सितंबर के उत्तरार्ध में चलनिधि के अंतर्वेशन में उल्लेखनीय गिरावट आई जो मुख्यतः सरकार की नकद शेष राशि में गिरावट आने की वजह से थी। अग्रिम कर का भुगतान, ऋण की मांग में मौसमी वृद्धि तथा त्योहार के मौसम में मुद्रा की मांग के अस्थायी दबावों के कारण चलनिधि के अस्थायी दबाव का अनुमान करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2012 में सीआरआर में 25 आधार अंकों की कटौती की जिससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹170 बिलियन के प्राथमिक चलनिधि का अन्तर्वेशन हुआ। अग्रिम कर के संबंध में बैंकिंग प्रणाली से राशि के बहिर्वाह के कारण औसत दैनिक निवल चलनिधि अंतर्वेशन की राशि सितंबर 2012 के उत्तरार्ध में बढ़कर ₹700 बिलियन से भी अधिक हो गई जो सामान्यतः अग्रिम कर संग्रहण वाली तिमाही में होने वाली वृद्धि से कम थी। 2012-13 की दूसरी तिमाही में एकमुश्त खुला बाजार परिचालन के जरिए कोई खरीद नहीं की गई, हालांकि एनडीएस-ओएम के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की गई।

IV.6 अक्टूबर 2012 के पहले सप्ताह में चलनिधि की कमी की स्थिति सहज हुई, परंतु माह के दूसरे सप्ताह से कमी में बढ़ोतरी हुई। चलनिधि में कमी की स्थिति में वृद्धि मुख्यतः बैंकों की रिजर्व की आवश्यकता की मांग में बढ़ोतरी होने एवं रिजर्व बैंक में सरकार के अधिशेष में बढ़ोतरी होने के बारे में बैंकों द्वारा सामान्य से कम एहतियाती उपाय किए जाने के कारण हुई। 1-24 अक्टूबर 2012 के दौरान चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत डाली गयी औसत दैनिक निवल चलनिधि की राशि ₹580 बिलियन थी।

IV.7 समग्र रूप में 2012-13 की दूसरी तिमाही में बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के दबाव में कमी आयी। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि बैंकों ने इस दौरान सीमान्त स्थायी सुविधा का लाभ कम मात्रा में लिया। अग्रिम कर के संबंध में बहिर्वाह होने एवं अप्रैल 2012 से सीमान्त स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार की सीमा में बढ़ोतरी किये जाने के बावजूद सितंबर 2012 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने सीमान्त स्थायी सुविधा का लाभ नहीं लिया। इसके अतिरिक्त, मासिक औसत मांग दर, जो नवंबर 2011 से जुलाई 2012 के दौरान रिपो दर एवं सीमान्त स्थायी सुविधा दर के बीच चल रही थी, में बाद में गिरावट आयी तथा अगस्त 2012 से वह मुख्यतः रिपो दर के नीचे

चार्ट IV.3: एलएफएफ का दायरा और मांग दरें



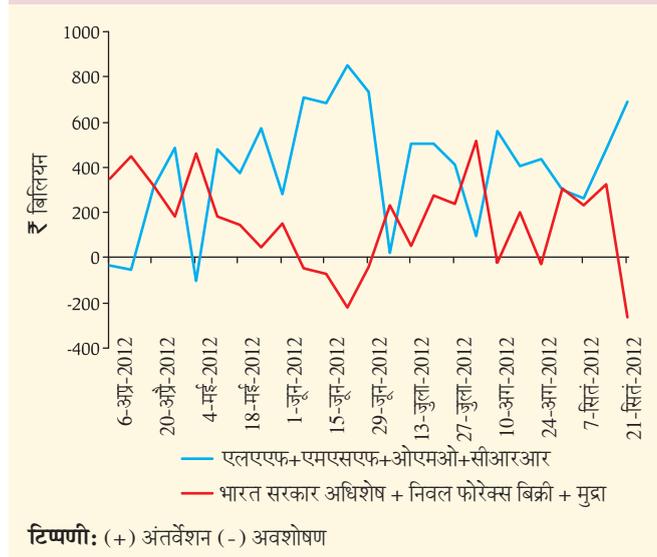
बनी रही। इसके अतिरिक्त इस वित्तीय वर्ष में अब तक मांग दर के उतार-चढ़ाव में तेज गिरावट आयी जैसा कि माह के दौरान दर में उतार-चढ़ाव के मानक विचलन से स्पष्ट होता है (चार्ट IV.3)।

IV.8 सामान्यतः रिज़र्व बैंक के बारीकी से समायोजित चलनिधि प्रबंधन संबंधी उपायों ने तीन समसामयिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान किया। इन चुनौतियों में ऋण के प्रवाह को बनाये रखना, नीति के उद्देश्यों का सुगमता से अंतरण एवं परिचालनीय दर को नियमित रखना शामिल है। चलनिधि के उचित प्रबंधन ने एक आधार उपलब्ध कराया ताकि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह बना रहे। इसने एक ओर जहां यह सुनिश्चित किया कि चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत आहरित राशि मोटे तौर पर एनडीटीएल के (+/-) 1 प्रतिशत के सांकेतिक दायरे में रहती है ताकि मौद्रिक नीति का संप्रेषण सुचारु रूप से हो सके, वहीं मुद्रा बाजार दरों के उतार-चढ़ावों में आयी कमी इष्टतम मौद्रिक नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालनात्मक ब्याज दर को व्यवस्थित बनाये रखने के केंद्रीय बैंक की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

2012-13 की दूसरी तिमाही में रिज़र्व मुद्रा में कमी आयी

IV.9 2012-13 की दूसरी तिमाही के दौरान रिज़र्व मुद्रा में स्पष्ट कमी आयी। घटक पक्ष में जहां परिचालन में स्थित मुद्रा की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) में गिरावट आयी वहीं रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमाराशि (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि में कमी आयी और यह वित्तीय वर्ष में अब तक ऋणात्मक रही। बैंकों की जमाराशि में आयी यह

चार्ट IV.4: चलनिधि के प्रबंधक के नियंत्रक



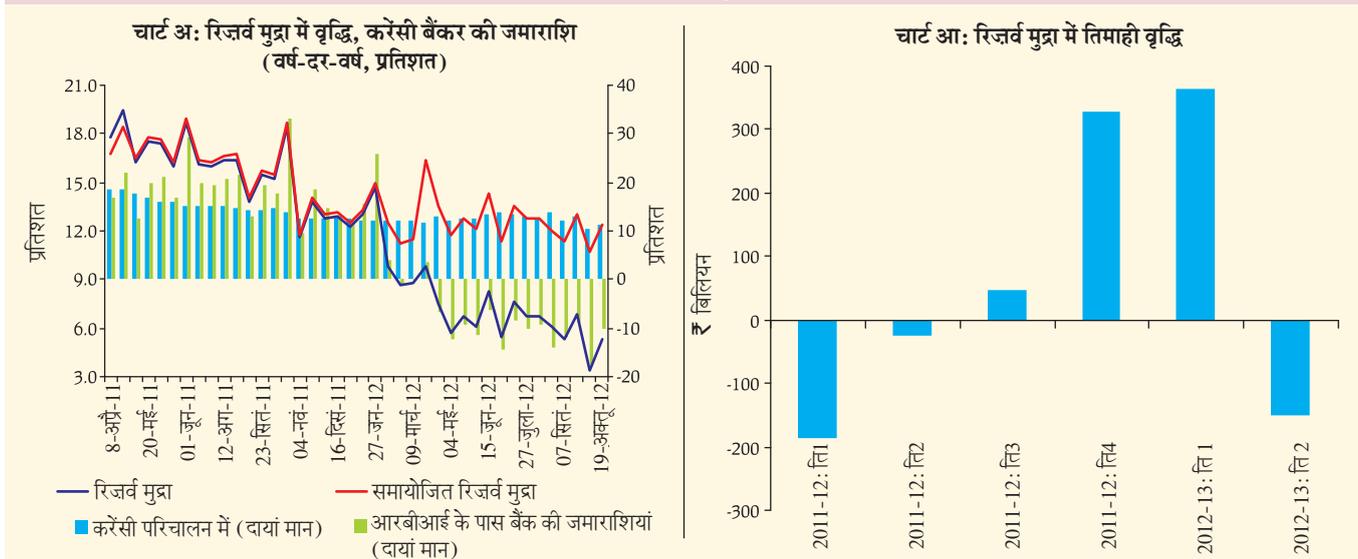
टिप्पणी: (+) अंतर्वेशन (-) अवशोषण

कमी मुख्यतः जब्त की गयी चलनिधि में गिरावट को दर्शाती है तथा इस प्रकार यह चलनिधि की स्थिति में सहजता को भी दर्शाती है जैसा कि जनवरी 2012 से सीआरआर में 150 आधार अंकों की कटौती से चलनिधि की स्थिति के सहज होने का अनुमान किया गया था। सीआरआर समायोजित रिज़र्व मुद्रा (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि अपेक्षातया स्थिर रही तथा यह वित्तीय वर्ष में अब तक 12.5 प्रतिशत के आसपास रही, फिर भी यह 2011-12 की तदनु रूप अवधि के 16.5 प्रतिशत से नीचे रही (चार्ट IV.5 तथा सारणी IV.2)।

2012-13 में व्यापक मुद्रा में निरंतर वृद्धि हुई परंतु यह निदर्शात्मक दायरे से नीचे रही

IV.10 इस वित्तीय वर्ष में अब तक मुद्रा की आपूर्ति (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर लगभग 13.6 प्रतिशत के आसपास रही। जहां रिज़र्व मुद्रा में आई गिरावट के चलते व्यापक मुद्रा की वृद्धि दर में गिरावट आई वहीं मुद्रा गुणक में हुई वृद्धि ने, विशेष रूप से 2012-13 की दूसरी तिमाही में, मौद्रिक विस्तार को बनाए रखने में योगदान दिया। 2012-13 की दूसरी तिमाही में मुद्रा गुणक की वृद्धि के कारणों में मुद्रा-जमाराशि अनुपात तथा बैंकों की जमाराशि की तुलना में सकल जमाराशि अनुपात में कमी आना था। 22 सितंबर 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से सीआरआर में की गयी कटौती से सकल जमाराशि की तुलना में बैंकों की जमाराशि के अनुपात में और गिरावट आयी जिसके चलते मुद्रा गुणक में वृद्धि हुई (चार्ट IV.6)।

चार्ट IV.5: रिज़र्व मुद्रा में कमी



सकल जमाराशि तथा ऋण वृद्धि में कमी आयी

IV.11 घटक पक्ष में वर्ष-दर-वर्ष सकल जमाराशि की वृद्धि दर में गिरावट आयी। इसकी प्रवृत्ति मुख्यतः मीयादी जमाराशि, कुल जमाराशि में इसका हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत होता है, के अनुरूप रही। 2011-12 के दौरान घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत दर में आयी गिरावट बैंक जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र की धारिता में आयी कम वृद्धि दर को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मीयादी जमाराशियों की

कम ब्याज दरों तथा वैकल्पिक आस्तियों (जैसे स्वर्ण) के अपेक्षाकृत उच्च प्रतिलाभ के चलते हो सकता है कि मीयादी जमाराशियों की वृद्धि दर में गिरावट आयी हो (IV.7)। दूसरी तिमाही के अंत में सकल जमाराशि में आयी तेज गिरावट का कारण 7 सितंबर 2012 से विभिन्न बैंकों द्वारा जमाराशि दरों में की गयी कमी एवं बैंकिंग प्रणाली से अग्रिम कर के चलते हुआ बहिर्वाह हो सकता है। मौसमी प्रवृत्ति के अनुसार 2012-13 की दूसरी तिमाही में जनता के पास स्थित मुद्रा में गिरावट आयी।

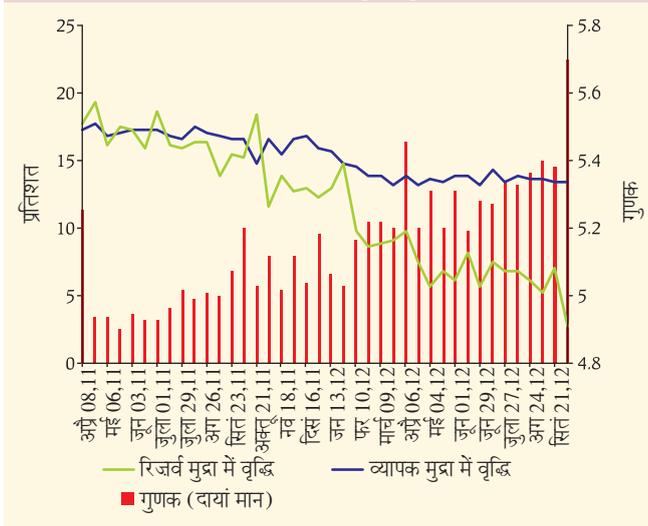
सारणी IV.2: मौद्रिक संकेतक

मद	बकाया राशि (₹ बिलियन) 05 अक्टूबर 2012	वित्तीय वर्ष में घट-बढ़ (प्रतिशत)		वर्ष-दर-वर्ष घट-बढ़ (प्रतिशत)	
		2011-12	2012-13	07 अक्टू 2011	05 अक्टू 2012
1	2	3	4	5	6
रिज़र्व मुद्रा (EM ₀)*	14,627.4	0.9	2.5	18.4	5.3
रिज़र्व मुद्रा (समायोजित)*		0.9	3.5	18.7	12.4
व्यापक मुद्रा (EM ₃)	79,118.8	7.4	7.5	16.6	13.3
EM₃ के प्रमुख घटक					
जनता के पास मुद्रा	10,545.0	4.2	2.7	13.9	11.0
कुल जमाराशियां	68,554.8	7.9	8.3	17.1	13.7
जिसमें से : मांग जमाराशियां	6,926.5	-9.1	-1.7	-2.8	5.4
मीयादी जमाराशियां	61,628.2	10.4	9.6	20.1	14.7
EM₃ के प्रमुख स्रोत					
सरकार को निवल बैंक ऋण	25,795.8	9.5	8.9	23.7	18.8
वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	51,696.0	5.6	4.2	19.4	15.6
बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां	15,462.2	11.0	0.2	14.9	0.0

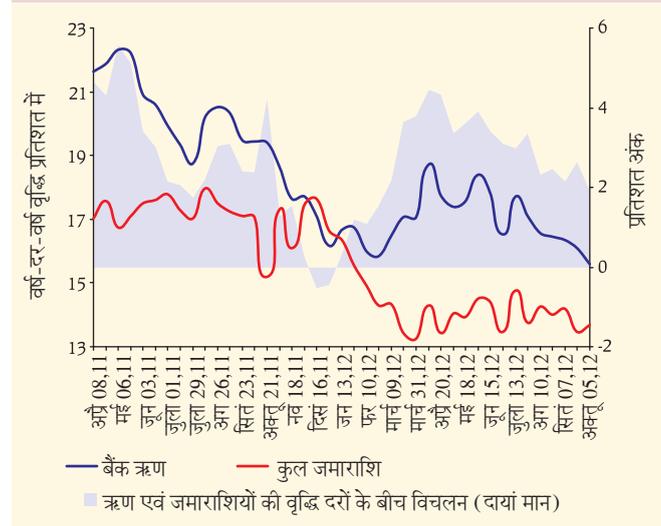
टिप्पणी: 1. आंकड़े अर्न्ततम हैं।

2.*: आंकड़े 19 अक्टूबर 2012 के हैं।

चार्ट IV.6: मुद्रा की आपूर्ति एवं रिजर्व मुद्रा में वृद्धि (व-द-व) तथा मुद्रा गुणक



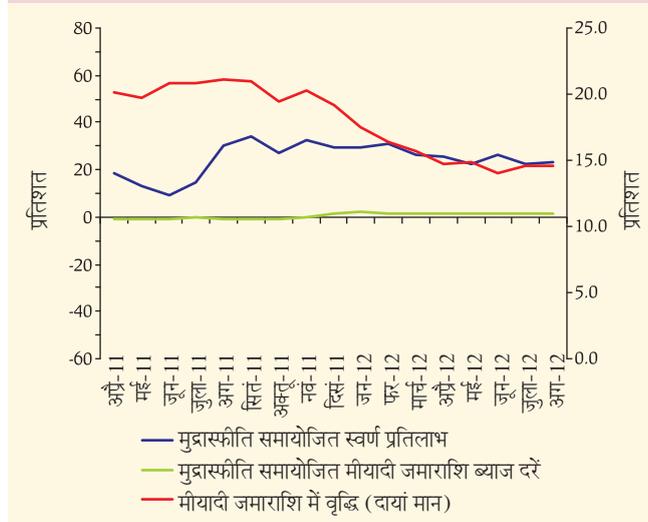
चार्ट IV.8: बैंक ऋण एवं सकल जमाराशियों के बीच अंतर



IV.12 2012-13 की दूसरी तिमाही में खाद्येतर ऋण की वृद्धि दर में गिरावट आयी जबकि पहली तिमाही में सामान्यतः वृद्धि हुई थी। इसका मुख्य कारण निवेश मांग में आयी गिरावट तथा ऋण की अधिक मांग करने वाले विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आना था। बैंक ऋण के वितरण में कमी आने के पीछे बैंकों की जोखिम की धारणा में बढ़ोतरी होना हो सकता है। ऋण तथा सकल जमाराशि की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के बीच सकारात्मक अंतर होने के बावजूद 2012-13 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में इस अंतर में कमी आयी। इन दो वृद्धि दरों के अंतर में आयी कमी ने 2012-13 की दूसरी तिमाही के

दौरान बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि में कमी लाने वाले ढांचागत कारको में से एक को रोकने में मदद की (चार्ट IV.8)।

चार्ट IV.7: वास्तविक प्रतिलाभ एवं मीयादी जमाराशि में वृद्धि (व-द-व)



IV.13 सितंबर 2012 के अंत में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋण की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) में गिरावट आयी। बैंक समूह के स्तर पर यह गिरावट सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में तेज थी। चूंकि बकाया ऋण की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंक सबसे बड़े उधारदाता हैं, अतः इनके ऋण की वृद्धि दर में गिरावट आने पर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समग्र ऋण-विस्तार में गिरावट आती है। विदेशी बैंकों के ऋण विस्तार में और अधिक गिरावट आयी। निजी क्षेत्र के बैंकों की ऋण वृद्धि दर सुदृढ़ रही जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में भी ऋण वृद्धि की दर सुदृढ़ रही थी (सारणी IV.3)।

IV.14 ऋण वृद्धि की दर में आयी गिरावट के कारणों में निवेश मांग में आयी गिरावट, आर्थिक कार्यकलापों में आयी कमी तथा उससे से भी अधिक महत्वपूर्ण बात, विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण की गुणवत्ता में आयी गिरावट रहे हैं। सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों के अनुपात एवं निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों के अनुपात में 2011-12 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और 2012-13 की पहली तिमाही में सभी बैंक समूहों में इसमें वृद्धि हुई (सारणी IV.4)। इन अनुपातों में हुई वृद्धि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामलों में सबसे अधिक थी और बैंक अग्रिमों में इनका हिस्सा प्रमुख होता है। गिरावट को दर्शाने वाला अनुपात, जो सभी क्षेत्रों में नये एनपीए में हुई वृद्धि को दर्शाता है, बैंकिंग क्षेत्र में अतिरिक्त जोखिम का संकेत करता है। 2012-13

सारणी IV.3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण

मद	05 अक्टूबर 2012* को बकाया राशि (₹ बिलियन)	घट-बढ़ (वर्ष-दर-वर्ष)			
		07 अक्टूबर 2011 को		05 अक्टूबर 2012* को	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1. सरकारी क्षेत्र के बैंक*	34,994.5	4,695.7	18.3	4,616.0	15.2
2. विदेशी बैंक	2,351.4	459.0	26.2	137.1	6.2
3. निजी बैंक	9,490.4	1,456.4	22.7	1,622.7	20.6
4. सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक@	48,093.9	6,766.1	19.5	6,597.2	15.9

* सरकारी क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर। @ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

की पहली तिमाही में मानक आस्तियों के पुनर्गठन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आस्तियों की गुणवत्ता एवं समष्टि आर्थिक स्थितियों में आयी गिरावट के चलते बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते ऋण सृजन के बदले सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम में बड़े स्तर पर भाग लेकर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके पोर्टफोलियो में बदलाव किया गया। सितंबर 2012 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों ने अपने एनडीटीएल का लगभग 28 प्रतिशत हिस्सा एलएलआर निवेशों में लगा रखा था।

IV.15 चुनिंदा बैंकों (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए कुल खाद्येतर ऋण में इनका हिस्सा 95 प्रतिशत से अधिक है) के सितंबर 2012 के आंकड़ों के आधार पर ऋण के क्षेत्रवार नियोजन के एक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में उद्योगों, सेवाओं तथा निजी ऋण के क्षेत्र को प्रदान किए गए खाद्येतर बैंक ऋण की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) में गिरावट आई। उद्योग को दिए गए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर सितंबर 2012 में 15.6 प्रतिशत थी जो सितंबर 2011 के 22.9 प्रतिशत से काफी कम है। उद्योग को दिए गए

ऋण में आई गिरावट, रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, सीमेंट तथा सीमेंट उत्पाद और कागज तथा कागज उत्पादों को छोड़कर, सभी प्रमुख उप क्षेत्रों में देखी गई।

वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर संसाधनों के प्रवाह में गैर-बैंक घरेलू स्रोतों का प्राधान्य रहा

IV.16 2012-13 के दौरान (5 अक्टूबर 2012 तक) वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में मामूली गिरावट आई। यद्यपि संसाधनों के प्रवाह में आई गिरावट बैंक तथा गैर-बैंक दोनों ही स्रोतों की वजह से थी, फिर भी वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत गैर-बैंक रहे (सारणी IV.5)। गैर-बैंक स्रोतों में इस वित्तीय वर्ष में अब तक घरेलू स्रोतों से प्राप्त निधियों में वृद्धि हुई जो मुख्यतः वाणिज्यिक पत्रों के अधिक मात्रा में जारी किए जाने एवं आवास वित्त कंपनियों द्वारा दिए गए निवल ऋण में वृद्धि होने की वजह से थी। परंतु वित्तपोषण के विदेशी स्रोतों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई (सितंबर 2012 तक) जो मुख्यतः बाह्य वाणिज्यिक उधार/ एफसीसीबी में

सारणी IV.4: बैंक समूह-वार एनपीए अनुपात

बैंक समूह	मार्च 2012					जून 2012				
	सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	स्लिपेज अनुपात#	सकल अग्रिम की तुलना में पुनर्संरचनागत मानक आस्ति (%)	सीआरएआर (%)	सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए (%)	निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए (%)	स्लिपेज अनुपात#	सकल अग्रिम की तुलना में पुनर्संरचनागत मानक आस्ति (%)	सीआरएआर (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सरकारी क्षेत्र के बैंक	3.17	1.47	2.95	5.74	13.23	3.57	1.75	3.49	6.67	12.78
विदेशी बैंक	2.68	0.61	2.35	0.10	16.74	2.90	0.83	2.43	0.08	15.72
सरकारी क्षेत्र के नए बैंक	2.18	0.44	1.17	1.06	16.66	2.19	0.45	1.31	1.06	16.11
सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	1.80	0.59	0.01	3.42	14.12	1.92	0.61	0.02	3.83	13.82
सभी बैंक *	2.94	1.24	2.60	4.69	14.24	3.25	1.45	3.04	5.37	13.74

स्रोत: अद्यतन किया गया ओएसएमओएस डेटाबेस.

* लैब शामिल हैं।

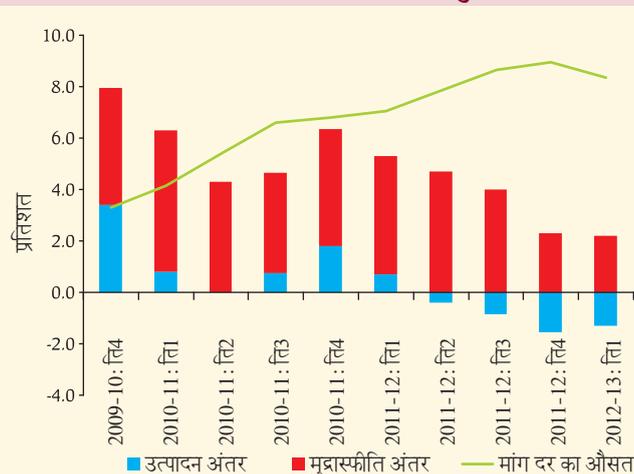
विशेष विश्लेषण के लिए बैंकों से प्राप्त किए गए डेटा पर आधारित। स्लिपेज अनुपात के जून 12 के आंकड़ों को वार्षिकीकृत किया गया है।

सारणी IV.5: वित्तीय संसाधनों का वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रवाह

(₹ बिलियन)

मद	अप्रैल-मार्च		1 अप्रैल से 5 अक्टूबर	
	2010-11	2011-12	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
अ. समायोजित खाद्येतर बैंक ऋण (एनएफसी)	7,110	6,764	2,296	2,138
i) खाद्येतर ऋण	6,815	6,525	2,086	1,871
जिसमें से: पेट्रोलियम और उर्वरक ऋण	-243	171	16	-94 ^
ii) एससीबी द्वारा गैर-एसएलआर निवेश	295	239	210	268
आ. गैर बैंकों से ऋण प्रवाह (आ1+आ2)	5,341	5,717	2,714	2,586
आ 1. देशी स्रोत	3,011	3,413	1,066	1,351
1. वित्तेतर संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम	285	45	40	63
2. वित्तेतर संस्थाओं द्वारा सकल निजी स्थानन	674	558	-	-
3. बैंक से इतर द्वारा अभिदान किए गए वाणिज्यिक पत्रों का निवल निर्गम	68	100	705	894 +
4. आवास वित्त कंपनियों द्वारा निवल ऋण	428	530	111	182 *
5. रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित 4 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं-नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एक्जिम बैंक-द्वारा प्रदत्त सकल सहायता	400	469	86	71 &
6. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशियां न लेने वाली एनबीएफसी (बैंक ऋण घटाकर)	795	1291P	-	-
7. एलआईसी का कारपोरेट ऋण, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक क्षेत्र में निवल निवेश	361	419	125	141 ^
आ 2. विदेशी स्रोत	2,330	2,304	1,648	1,235
1. बाह्य वाणिज्यिक उधार / एफसीसीबी	555	421	351	217 &
2. एडीआर / जीडीआर निर्गम, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर	92	27	13	9 ^
3. विदेश से अल्पावधि ऋण	502	306	137	291 #
4. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	1,181	1,550	1,147	718 ^
इ. संसाधनों का कुल प्रवाह (अ+आ)	12,451	12,481	5,010	4,724
ज्ञापन मदें:				
म्यूचुअल फंडों द्वारा ऋण (गिल्ट से इतर) योजनाओं के माध्यम से जुटाए गए निवल संसाधन	-367	-185	34	500 &
अ: अंतिम	&: सितम्बर 2012 तक	^: अगस्त 2012 तक	#: जून 2012 तक	
+: 24 सितम्बर 2012	*: जुलाई 2012 तक	-: उपलब्ध नहीं है		

चार्ट IV.9: मांग दर, उत्पादन अंतर और मुद्रास्फीति अंतर



टिप्पणी: अंतर का तात्पर्य संभावित वृद्धि दर और वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अंतर से है। संभावित वृद्धि दर का अनुमान एचपी फिल्टर का उपयोग करके किया जाता है। मुद्रास्फीति अंतर का तात्पर्य पांच प्रतिशत के सहज स्तर और तिमाही मुद्रास्फीति दर के अंतर से है।

आई गिरावट तथा भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में आई गिरावट की वजह से थी।

वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिविधि के साथ विकसित हो रही मौद्रिक और चलनिधि स्थितियाँ

IV.17 परिचालन लक्ष्य की दिशा (भारत औसत मांग दर), जो नीति दरों का अनुसरण करती है, उत्पादन तथा मुद्रास्फीति अंतरों के अनुरूप रही है (चार्ट IV.9)। यद्यपि मुद्रास्फीति अंतर के चलते मौद्रिक नीति को सख्त किया गया था, परंतु आर्थिक गिरावट मौद्रिक कड़ाई के अलावा कई अन्य कारणों आ सकती है (अध्याय I देखें)। 2012-13 की दूसरी तिमाही के अधिकांश भाग में चलनिधि की स्थिति समुचित रहने के बावजूद खाद्येतर ऋण की वृद्धि दर में आई गिरावट अंशतः कमजोर वैश्विक मांग तथा जोखिम से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे बाहरी अथवा गैर-मौद्रिक कारकों की उपस्थिति का संकेत करती है।